in reinstating the victimised workers. But he cannot take shelter behind that one act all the time. What I have been saying is, why is it that he could not go one step further? Last time, in May, 1974 the discussions with the workers on their demands were left unfinished. He promised us bonus. What has happened to bonus? Is it because of the Bhoothalingam Committee which says, no bonus to the railwaymen? The Railway Minister has written to me saying that the railwaymen are better paid than anybody else if you take everything that they get into consideration and so on. So, let him not every time remind us of that one good act of reinstatement let him not take shelter behind that one good act. There are many distortions and abberations in the Railway Ministry which he has to look into.

For instance, why is it that the office bearers of the recognised federations get certain protection even when their transfer is suggested at the instance of the vigilance organisation? If this is correct, is it moral? Just because he is an office bearer of a recognised federation, even where the vigilance officer has come out with a report against him, he gets protection in the matter of transfer. Is it proper? I want to bring to his notice thousand and one things that are happening in the huge jaggernant Rail Bhavan. Of course, one man cannot do everything. I am not accusing him. All those sections of workers who are in a position to act in an organised way, you do lend a hearing to them. But I do not think you always take action.

While talking about railway accidents, talking about human failures and the need to see that the demands of the railwaymen are satisfied, it is not that we say that they will be responsible for accidents if they do not get bonus. Not at all. But the fact remains that the demands of the railwaymen still remain unfulfilled. Certainly, when you give them their bonus, it is their just and right demand. When you sit down with them at the table and talk to them about their wage structure, then you will certainly find that many other problems also be brought to your notice. The efficiency of the railways can be increased and improved by taking the railwaymen the railway workers, more in confidence and by seeing that the officers do not continue to rule the roots based on rules under the Indian Railways Act of 1905.

MR. CHAIRMAN: Now, a substitute Motion has been moved by Shri Yuvraj: does he want withdraw it?

He is not present. Since he is not present in the House, I shall put his motion to the vote of the House.

The substitute Motion was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The discussion has now concluded. Let us take up Half-an-Hour Discussion now.

18.31 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

FALL IN SUGARCANE PRICE

श्री रामानन्द तिवारी (बकसर) : सभापति जी प्रश्न संख्या 4 के 17 जुलाई, 1978 को दिये गये उत्तर पर विचार करने के पहले मैं सरकार के मंत्रियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने प्रश्नों के उत्तर आते हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेसी छायी हुई है, वह मंत्रियों के मुख से गलत उत्तर कहलवाते हैं। अगर ये गलत नहीं कहलवाते, तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यही नहीं, तारांकित प्रश्न जितने जाते हैं, उनमें से 80 प्रतिशत के उत्तर भ्रामक, गलत और अस्पष्ट होते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे मंत्री नौकरशाहों के एडवोकेट जनरल हैं, जब कि उन्हें जनता का होना चाहिये।

[श्री रामानन्द तिवारी]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। हम जानते हैं कि पहले 30 बरसों तक कांग्रेसी हुकूमत में जो गन्ने का प्राइस, कीमत निश्चित की जाती थी, सपोर्ट प्राइस, समर्थन न्यूनतम कीमत, उसके लिये किसान का प्रतिनिधि, मिलमालिक, को-आपरेटिव और सरकार के प्रतिनिधि, ये मिलकर कम-से-कम कीमत निश्चित करते थे। 30 बरसों तक कांग्रेसी सरकार, जब पैसे की उसे आवश्यकता होती थी तो उसका झुकाव मिल मालिकों की तरफ हो जाता था और जब वोट की बात आती थी, तो उसका झुकाव किसानों की तरफ हो जाता था, लेकिन इस परम्परा को जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ा है। इसलिये मैं उसको बधाई देता हूं क्योंकि इस बार प्रति क्विंटल मिनिमम कीमत 10 रुपये की है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिये कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति क्या है। इस पर भी इनको विचार करना चाहिये।

सब से पहले मैं कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह सदन में यह आंकड़ा प्रस्तुत करें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रति वर्ष एक एकड़ में गन्ने के उत्पादन पर कितनी लागत का खर्च पड़ता है? जब तक यह नहीं कर पायेंगे, हम सरकार से अपील करते हैं कि सदन में वह प्रस्तुत करें कि लागत खर्च कितना आ रहा है? अगर सरकार के पास यह नहीं है तो भी स्पष्ट कहें। यदि उनके पास नहीं होंगे तो हम उनको लाकर देंगे, क्योंकि इनका सम्बन्ध सीधे किसानों से नहीं है, हमारे जैसे कार्यकर्ता का सीधा सम्बन्ध किसानों से है।

उसके बाद हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे देश में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कितना गन्ना उत्पादन होता है? इसके आंकड़े भी कृपा कर बतलाने का कष्ट करें, तब हम समझेंगे कि आपने जो दाम निश्चित किये हैं उसका आधार और बुनियाद क्या है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों अभागे प्रांत हैं, हिन्दुस्तान के सब से पिछड़े हुए, सबसे गरीब प्रांत हैं, जहां की 70 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीचे है। इन दोनों प्रांतों का विकास नहीं हुआ है। वहां इंडस्ट्री का अभाव है, कोई उद्योग-धंधा नहीं है। परिणामस्वरूप वहां के गरीब कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास या अन्य स्थानों में पचास, सौ, डेढ़ सौ या दो सौ रुपये माहवार वेतन पर नौकरी करने जाते हैं।

बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सब से प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग है। यदि इस उद्योग का अहित हुआ, यदि यह इंडस्ट्री बर्बाद हुई, तो फिर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी भयंकर हो जायेगी कि सरकार उसको संभाल नहीं सकेगी। बिहार में चीनी मिलें 1930 में चलनी प्रारंभ हुई। मगर आज स्थिति यह है कि दर्जनों फैक्टरियां बंद हैं, हजारों मजदूर बेकार हैं और दाने-दाने के लिए मुहताज हैं। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि इस का परिणाम क्या होगा।

यह कितनी लज्जा और शर्म की बात है कि माननीय राज्य कृषि मंत्री ने कहा कि हमें यह जानकारी नहीं है कि ईख जलाई गई है। मैं उन को बताता हूं—मैं उन्हें चुनौती देता हूं—कि राज्य कृषि मंत्री के अपने जिले में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ईख जलाई गई है। वह मेरे साथ चलें चम्पारन, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि जो गरीब किसान जेठ की तपती धूप में मेहनत कर के ईख पैदा करता है, जब माननीय राज्य कृषि मंत्री जी और हमारे जैसे लोग एयर-कंडीशन में बैठे रहते हैं, तब जो किसान पानी में भीग कर, जाड़े में ठिठुर कर, ईख पैदा करता है, उसी विषय में

कर ईख जलानी पड़ती है। इससे आगे कर्ज खरचा और कर्ज की बात क्या होगी? इसलिए मैं मंत्री महोदय से पुनः अपील करना चाहता हूं कि वह इस बारे में पूरी छान-बीन करायें, सोचें और चिन्तन करें कि वह अभागे बिहार, दुखी पीड़ित बिहार, निर्धन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को और दुखी न करें। पिछले तीस बरसों में कांग्रेसी शासन ने इन दोनों प्रान्तों को बर्बाद किया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब जनता पार्टी की सरकार इन प्रांतों के साथ उचित न्याय करेगी। उसने अभी गन्ने की कीमत बढ़ाई है और इस प्रकार पिछले शासन की इस परम्परा को तोड़ दिया है कि पैसे के लिए पूंजीपतियों पर निर्भर करें और वोट लेने के लिए आम जनता के पास जायें। मुझे आशा है कि वह आगे भी इसी नीति पर चलती रहेगी।

इससे भी गंभीर स्थिति यह है कि गरीब किसानों का एक अरब रुपया मिल-मालिकों के यहां बाकी है। हम जानना चाहते हैं कि इसका क्या कारण है कि सरकार गरीब किसानों का एक अरब रुपया नहीं दिला रही है, जो खाने-खाने के लिए मुहताज हैं। क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि जो मिल-मालिक उचित समय पर पैसा नहीं देते हैं, जो एक अरब रुपया नहीं लौटाते हैं, उन मिल-मालिकों को यह आदेश दिया जाये कि वे पन्द्रह दिनों के भीतर पैसा दें, वर्ना उनको पकड़ कर उस वक्त तक जेल में बन्द किया जाये, जब तक कि वे पैसा वापस नहीं देते हैं? आखिर यह सरकार मिल-मालिकों के बल पर नहीं बनी है, बल्कि यह किसानों और खेतिहर मजदूरों के बल पर बनी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस पर विचार करें।

अन्तिम निवेदन यह करना चाहता हूं कि मैं यह नहीं चाहता हूं कि गन्ने का उत्पादन इतना अधिक हो जाय कि जिसका परिणाम यह हो कि गल्ले का उत्पादन कम हो जाय। इसलिए आपको मार्गदर्शन करना है, चिन्तन करना है कि किन-किन जमीनों पर ... स्थिति में हम अधिक से अधिक गन्ने के उत्पादन करेंगे। यह सीमा आप को बतानी है, यह मार्गदर्शन आपको करना है। यह हम इसलिए चेतावनी देना चाहते हैं कि हम यह नहीं चाहते कि एक ही फसल का उत्पादन हो क्योंकि हमें और फसलें चाहिए। अगर उनका उत्पादन नहीं होगा तो हमें विदेश से आयात करना पड़ेगा। उसे भी हमें रोकना है क्योंकि इस गरीब देश को स्वावलम्बी बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से कहना चाहता हूं कि आप मार्गदर्शन करें किसान का और एक सीमा निश्चित कर दें कि इस तरह की जमीन, इस तरह का पानी, इस तरह का वातावरण जहां होगा वहां हम इतना अधिक से अधिक ईख का उत्पादन करेंगे जिसका कि उचित मूल्य आप दे सकें। हम आशा और विश्वास करते हैं अपनी बात समाप्त करते हुए कि इस पर आप चिन्तन-मनन करेंगे। लेकिन फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि इस सदन का समय बरबाद न करें। आप उन नौकरशाहों से, ब्यूरोक्रेट्स से सावधान रहें जो आपके मुख से गलत बात कहलवाना चाहते हैं। असत्य कहना असंसदीय होगा, इसलिए असत्य न कहते हुए मैं यह कह रहा हूं कि जो आपके मुख से और सरकार के मंत्रियों के मुख से गलत बात कहलाना चाहते हैं। आप बड़ी सावधानी के साथ चलें। मैं भी मंत्री रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि हमारे अधिकारी किस तरह से गलत कराते थे और जो स्टार्ड या अनस्टार्ड क्वेश्चन आते थे उसको देख कर फिर लौटाते थे। सदन में हम समय लेते हैं लेकिन हमें दुख है, व्यथा है, इस परम्परा को कांग्रेसियों ने चलाया, आप इस परम्परा पर मत चलें, आप सरकारी अधिकारियों के वकील न बनें, उनके एडवोकेट जनरल न बनें, आप सदन के बनें, जनता के बनें, एक नयी परम्परा कायम करें। इस ब्यूरोक्रेसी को इतना शक्तिशाली न बनाएं कि आप उनके हाथ में खिलौना हो जायें और

[श्री रा रामानन्द तिवारी]

...त जानते हुए भी उनकी तरफ से वकालत करें । इसलिए आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक स्वस्थ परम्परा रखें जिसमें अधिक से अधिक सत्य सामने आ सके । मैं पूरा सत्य इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं जानता हूं कि आज हमारे देश की हालत क्या है, हमारा चरित्र क्या है, हमारा मनोबल क्या है और हमारी नैतिकता क्या है ? उसी में से आप आए हैं । मंत्री हैं, आप देवता नहीं हैं । आपका उद्गम स्थान वही है जहां से हमारे सरकारी अधिकारी हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, और हम संसद सदस्य हैं । इसी में से आप मंत्री बने हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे सरकारी अधिकारियों का उद्गम स्थान भी वही है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे दुख है मैं आपके माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि मत सदन का समय नष्ट करो, मत मंत्रियों के मुंह से गलत बात कहलाने का प्रयास करो, मत उन्हें अपना वकील बनाओ। जनता जिसकी गाढ़ी कमाई से आपका भरण-पोषण होता है उसका ख्याल करो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा और विश्वास करता हूं कि माननीय कृषि मंत्रीजी हमारी बातों पर ध्यान देंगे । यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): I am thankful to Mr. Tiwary for raising up this debate.

उन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं । मैं यत्न करूंगा उनका जवाब देने का । उन्होंने बिहार और यू० पी० के बारे में कुछ आंकड़े मांगे कि वहां पर स्थिति क्या है, गन्ने की पैदावार क्या हुई है ? जहां तक इस वक्त देश में टोटल गन्ने की पैदावार का ताल्लुक है उसके बारे में तो मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले साल 154 मिलियन टन गन्ना हुआ था और इस वक्त 172 मिलियन टन गन्ना हुआ है । यानी तकरीबन 18 मिलियन टन पिछले साल से ज्यादा हुआ है और इसमें अगर सारे देश का हिसाब लगाएं तो कोई सवा ग्यारह परसेंट गन्ने की पैदावार बढ़ी है, लेकिन अकेले यू० पी० में 17 परसेंट के करीब बढ़ी है । इसलिए यू० पी० में गन्ने की पैदावार इस दफा ज्यादा हुई है । यू० पी० की गन्ने की पैदावार मैं आपको सारी बृंगा । पिछले साल खाण्ड और चीनी की कुल पैदावार 48.43 लाख टन हुई थी और इस दफा तकरीबन 65 लाख टन हुई है । इस तरह के हिसाब के मुताबिक 19 मिलियन टन गन्ना ज्यादा कल हुआ है क्योंकि शुगर उसी हिसाब से बनी है । गन्ने की पैदावार 18 मिलियन टन ज्यादा हुई । और गन्ने की क्रशिंग 19 मिलियन टन ज्यादा हुई । इस तरह का यह हिसाब है । यह फीगर आज से कोई 15 दिन पहले तक की हैं क्योंकि अभी भी चार-पांच मिलें चल रही हैं ।

इस के बारे में कुछ बिहार एरिया के जो आंकड़े हैं वह मैं देना चाहूंगा । बिहार में 1975-76 में 1 लाख 33 हजार हेक्टर में गन्ना पैदा हुआ और 1976-77 में 1 लाख 27 हजार 800 हेक्टर में गन्ना पैदा हुआ और प्रोडक्शन 1975-76 में 49 लाख टन हुआ, 1976-77 में 41 लाख 75 हजार टन हुआ । यह प्रोडक्शन फीगर्स हैं ।

दाम जो मिले हैं वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा । मैं उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जो दाम मिले वह बताऊंगा । वेस्ट यू०पी० में इस साल गन्ने की जो कुल ग्राइस मिली किसानों को वह है 87 करोड़ एक लाख 36 हजार रुपया । सेन्ट्रल यू०पी० में 108 करोड़ 6 लाख 43 हजार का गन्ना बिका और ईस्टर्न यू० पी० में 64 करोड़ 52 लाख 16 हजार का गन्ना बिका । इस तरह से यू०पी० में टोटल 259 करोड़ 60 लाख 95 हजार का गन्ना बिका ।

बिहार के आंकड़े इस प्रकार से हैं। कुल गन्ना जो किसानों ने पैदा किया वह है 38 करोड़ 16 लाख 91 हजार टन। अब उन्होंने मुझ से सवाल किया था कि बहुत सा पैसा बकाया पड़ा है किसानों का तो उस के बारे में भी मैं अलग-अलग बता देना चाहूंगा। सवाल बिहार और यू०पी० का किया गया था। मैं टोटल आंकड़े भी दे दूंगा। बिहार में बकाये की इस वक्त 15-7-78 तक की फीगर्स है। बिहार में बकाया 1 करोड़ 73 लाख 56 हजार रुपया है। वेस्टर्न यू० पी० में बकाया 21 करोड़ 51 लाख, सेन्ट्रल यू०पी०में 24 करोड़ 32 लाख और ईस्टर्न यू० पी० में 6 करोड़ 36 लाख—इस तरह से यू०पी० में टोटल 52 करोड़ 19 लाख 95 हजार रुपया बकाया है।

जो भी करोड़ रुपए की बकाया मैं ने बताई उसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं। 15 मई को 104 करोड़ का बकाया था। 31 मई को यानी 15 दिन बाद 100 करोड़ 11 लाख का बकाया रहा। 15 जून, को 94 करोड़ 21 लाख का बकाया रहा और 30 जून को 84 करोड़ 16 लाख का बकाया रहा। उसके बाद 15 जुलाई को 81 करोड़ 60 लाख का बकाया था। इस तरह से इस में 15.3 फीसदी की कमी आई। यह पोजीशन मैं ने 15 जुलाई तक की बताई है। इस हिसाब से बकाया 104 करोड़ से कम हो कर 15 जुलाई को 81 करोड़ 60 लाख तक आया। इस बार चीनी की पैदावार बहुत ज्यादा हुई...

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : एक सूचना आपने नहीं दी—यह कब से बकाया है?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं यह भी आप को बताऊंगा—पिछले पीरियड का जो केन-अरियर का फिगर है, वह इस तरह है—1975-76 में यह बकाया 6 करोड़ 35 लाख 60 हजार रुपए थे। अब जहां तक इस के हिसाब का ताल्लुक है—कि यह बकाया कैसे है—मैंने इस को डिस्कस किया था, इसके बारे में अलग-अलग रायें हैं। जो जानकारी मुझे मिली है—उस में कहा गया है कि इस में बहुत सी यह रकम है जो अन-क्लेम्ड है, जिस को लेने के लिए लोग नहीं आते हैं. इसी लिए यह रकम पड़ी हुई है....(व्यवधान).....

श्री रामधारी शास्त्री : यह गलत है, यह रकम उन को दी ही नहीं गई, वे लोग चक्कर लगाते रहे.....(व्यवधान)....

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मेरे पास जो जानकारी है, वह मैं आप के सामने रख रहा हूं—उस से आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

मैं अर्ज कर रहा था—1975-76 में जो बकाया था, वह 6 करोड़ 35 लाख 60 हजार था। 1976-77 में 2 करोड़ 18 लाख रहा और इस साल 15 जुलाई तक का मैं ने अर्ज किया है—81 करोड़ 60 लाख बनता है।

देश में जो प्राइस रही है, उस के मुकाबले इन्टरनेशनल प्राइस कम रही है। अब गन्ने की पैदाइश ज्यादा हुई, तो यह कोशिश की गई कि शुगर ज्यादा पैदा की जाय, क्योंकि जितना ज्यादा गन्ना क्रश होगा, उस से ज्यादा शुगर पैदा होगी और गन्ने की कीमत भी ज्यादा होगी। गन्ने की कीमत भी इस साल पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा रही है। उस के आंकड़े भी मेरे पास हैं। पहले 30 पर-सेंट गन्ना क्रश होता था...

श्री रामधारी शास्त्री (पडरौना) : आंकड़े बहुत हो गए।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मुझ से मांगे गए हैं, इस लिए बतला रहा हूं। मैं बहुत

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

बुलकुल आंकड़े हैं, शायद आप के काम आयें ।

केन-फैक्टरीज में कितना गन्ना जाता है—सब से पहले उस के कुछ आंकड़े देना चाहूंगा—मैं ने इन को 1973-74 में इकट्ठा किया हुआ है। 1973-74 में 42 मिलियन टन गन्ना क्रश हुआ। 1975-76 में 41.9 मिलियन टन क्रश हुआ। 1976-77 में 48.9 मिलियन टन क्रश हुआ और इस साल 67 मिलियन टन क्रश हुआ। इस की परसेन्टेज इस तरह है— 1973-74 में 30 परसेन्ट टोटल प्रोडक्शन का क्रश हुआ, 1974-75 में 33 परसैन्ट क्रश हुआ, 1976-77 में 29.9 परसैन्ट हुआ, जोकि पहले से कम था और पिछले साल 31.7 परसेन्ट हुआ, लेकिन इस साल 39 परसन्ट गन्ना क्रश हुआ और इसके लिए हमें काफी कोशिश करनी पड़ी ताकि यह गन्ना ज्यादा से ज्यादा क्रश हो सके।

यह भी कहा गया कि हमारे स्टेट मिनिस्टर यहां कह गए हैं कि कोई गन्ना खड़ा नहीं रह गया है—उस के आंकड़े भी मुझ से मांगे गए हैं। जो आंकड़े मुझे प्रान्तों से मुयस्सर हुए हैं—ये पिछले 15 दिन तक के आंकड़े हैं—गुजरात में 25 हजार टन रहा, हरयाणा में 11,500 टन, महाराष्ट्र में 66 हजार टन, यू० पी० में 1.9 लाख टन, तामिलनाडू में 2 लाख 10 हजार टन—तामिलनाडू में क्रशिंग सीजन बाद तक चलता है, अभी भी वहां पर कुछ फैक्टरीज चल रही हैं, उन का क्रशिंग सीजन लेट होता है। आपसे मैं ने पहले अर्ज किया कि बिहार के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं क्योंकि वे मुझे नहीं मिले हैं ये जो आंकड़े मैंने दिए हैं ये 15 दिन पहले के आंकड़े हैं।

इस के हिसाब से जब शुगर की प्रोडक्शन ज्यादा हुई और वह शुगर मिलों के पास पड़ी रही और उनकी तरफ केन का बकाया बहुत ज्यादा हो गया, तो हमें उन मिलों की सारी हालत को देख कर के यह फैसला करना पड़ा कि चीनी का डीकन्ट्रोल कर दिया जाए ताकि इसकी कंजम्प्शन बढ़ सके। पिछले साल भी हमने इसकी कंजम्प्शन बढ़ाने की कोशिश की थी लेकिन 23 परसेंट तक ही कंजम्प्शन बढ़ सकी। इसको हम बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। जब प्राइसिज नीचे आयेंगी तभी कंजम्प्शन बढ़ेगा। अभी जो वातावरण बना है, उसके हिसाब से प्राइसिज नीचे आ रही हैं। इससे कंजम्प्शन बढ़ेगी, ऐसी हमें उम्मीद है।

कंजम्प्शन बढ़ने से सरप्लस स्टाक बाजार में जाएगा और इससे शुगर मिल वाले केन की प्राइसिज भी अदा कर सकेंगे। जो केन प्राइसिज अदा नहीं कर सकते हैं उनको 15 परसेंट जुर्माना देना पड़ता है। हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है कि वे जल्दी से जल्दी केन की प्राइसिज अदा करायें।

श्री राम किशन (भरतपुर): माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया, चीनी के भाव जिस प्रकार से नीचे आ रहे हैं. उससे तो स्पष्ट है कि सरकार ने जो गन्ने की सपोर्ट प्राइस तय की है, उस पर गन्ना नहीं बिकेगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि खेती की पैदावार, के दाम इन दो सालों में निरन्तर गिर रहे हैं लेकिन खेती के उपादान में जो चीजें काम में आती हैं—जैसे ट्रैक्टर्स हैं, पेस्टीसाइड्स हैं, खाद वगैरह हैं, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, क्या सरकार इनकी कीमतें घटाने की कोई योजना रखती है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जैसा आपने कहा कि गन्ने की कीमत नहीं मिल सकेगी, तो

मैं बताना चाहता हूं कि यह पहली दफा ऐसा हुआ है जब कि दस रुपये प्राइस रिलेटिड टू 8.5 की गयी है। मार्च तक 8 रुपये 50 प्राइस रही है। हम ने थोड़ा ज्यादा रिकमण्ड की थी लेकिन उसको माना नहीं गया। यह पहली दफा 8.5 रिकवरी पर दस रुपये प्राइस रखी गयी है। हमें पूरी उम्मीद है कि यह प्राइस मिलेगी।

जहां फैक्टरी एरिया है वहां तो कहीं शुगर केन की प्राइस 13 रुपये रही है, कहीं साढ़े तेरह रही है। कहीं साढ़े बारह रुपये भी चलती रही है। लेकिन जहां गन्ना पैदा होता है और वहां फैक्ट्री एरिया नहीं है तो वहां प्राइस जरूर कुछ कम है। वहां लोगों को शुगर केन कोल्हसारी के लिए ले जाना पड़ता है या कमर के पास गुड़ बनवाने के लिए ले जाना पड़ता है। फैक्ट्री एरिया में इस किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। वहां तो प्राइस अच्छी रही है। इस्टर्न यू० पी० में साढ़े बारह रुपये, वेस्टर्न यू० पी० में साढ़े तेरह रुपये और बिहार में साढ़े बारह रुपये के करीब प्राइस चली है। पिछले साल से गन्ने की कीमत में कमी नहीं हुई है। यह कहीं 25 पैसे पर क्विंटल ज्यादा थी, कहीं 25 पैसे प्रति क्विंटल कम थी।

श्री राम किशन : मैं ने खेती के काम में आने वाली चीजों के दामों के बारे में भी पूछा था।

श्री राम अवधेश सिंह (बिक्रमगंज) : इन्होंने पूछा था कि कृषि उत्पादन में जो सामान लगता है — जैसे ट्रैक्टर हैं, खाद है, इन के दाम बढ़ते आ रहे हैं और कृषि उत्पादन के दाम गिरते जा रहे हैं। इन के बीच में कोई मेल बिठाने का कोई काम किया जाएगा। इस बारे में इन्होंने जवाब नहीं दिया।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह जनरल क्वेश्चन है यह जनरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का सवाल है कि जो खेती की पैदावार होती है, उसमें जो कुछ लगता है, उसमें जो इनपुट्स लगता है वह मंहगा हो गया है। कुछ ऐसा उनका कथन है। जहां तक खाद का ताल्लुक है खाद की कीमत पिछले साल हम ने सौ रुपये कम की थी। यूरिया की कीमत 1650 रुपये थी जिसको कम कर के 1550 रुपया मुकर्रर किया गया। इससे किसान को करीब चालीस करोड़ रुपये का लाभ हुआ। आंकड़े भी मेरे पास हैं और मैं आपको दे सकता हूं।

19.00 hrs.

जहां तक दूसरी इनपुट्स का ताल्लुक है उन में से बहुत सी का स्टेट्स से ताल्लुक है। जैसे बिजली की दर को आप लें। पंजाब में इसको कुछ कम कर दिया है हरियाणा में भी क्या रेट कम की गई है? कई जगह पर यह बढ़ गई है। यह स्टेट का मामला है।

इसी तरह से लैंड रेवेन्यू की बात है। कहीं इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और कहीं कम कर दिया गया है। किसी स्टेट ने पांच एकड़ तक लैंड रेवेन्यु नहीं रखा है और किसी ने लगा दिया है। यह भी स्टेट्स से सम्बन्ध रखता है।

जहां तक ट्रैक्टर्ज की प्राइसिस का ताल्लुक है जो बड़े किसानों से ताल्लुक रखता है मैं मानता हूं कि उनकी कीमतें कुछ बढ़ी हैं। कई कारणों से वे बढ़ी हैं। हमने कोशिश की थी कि किसी तरह से उनको कम किया जा सके। लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली है। जल्दी सफलता मिलने की मुझे उम्मीद भी नहीं है। इस वास्ते ट्रैक्टर्स के दाम कम करने की बात मैं अभी नहीं कह सकूंगा क्योंकि मुझे ऐसी कोई आशा नहीं है।

SHRI CHITTA BASU (Barasat): I will put only specific questions. During this session also, this question was discussed in this House and the question was posed by the State Minister of Agriculture that the miseries of sugarcane growers in this current season is due to over-production, and the panacea suggested was to decrease the acreage of sugarcane field and according to me this is not a solution to the problem. There has been bumper crop, this time and there is less price for the sugar. But less of production in the coming years means again higher price for the sugarcane and also for the sugar in the market. That is no solution to the problem. May I know in this context, from the hon. Minister whether the Ministry of Agriculture has got any proposal to have an integrated plan for the development of sugarcane cultivation and also to remove this problem for all time to come?

My second question still remains unanswered. That is the question proposed by Mr. Ramanand Tiwari also that the Agricultural Prices Commission fixes the minimum support price and that it should take into account the cost of cultivation while fixing up the minimum support price. That question has not been answered by the Minister. I put it again now.

Thirdly, I would like to know whether he will take further steps in the matter of realisation of arrears due to the cane growers, which is about Rs. 81.0 crores, as stated by you. What steps are you taking to get the entire arrears cleared and whether any legislation is under consideration for realising these arrears? How many years will you take to get the entire arrears realised?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, I do not understand what type of integrated agricultural plan my hon. friend is suggesting for production of sugarcane. There cannot be any integrated project or plan for growing sugarcane in the country as such. Every State has its own different method or different type of growing sugarcane. In Bihar the sugarcane cultivation is slightly different from what is done in Maharashtra. In Maharashtra, the recovery is much more than in Eastern U.P. and Bihar and some of the northern States. There are many reasons for that. So, there cannot be any integrated plan as such but our effort has been that the best quality of sugarcane should be produced in different areas as required in those climatic conditions.

So far as the question how the price is fixed is concerned, some of the things that are taken into consideration are: (1) Cost of production; (2) the return to the growers from the alternative crops and general trends of prices of agricultural commodities; (3) the availability of sugar to the consumers at a fair price; (4) the price at which sugar produced from the sugarcane is sold by producers of sugar; and (5) the recovery of sugar from the sugarcane. All these are taken into consideration while deciding the minimum price. Accordingly, this year we have raised the minimum price from Rs. 8.5 to Rs. 10.00 per quintal.

MR. CHAIRMAN: Now, the time for this discussion is over. (Interruptions)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मेरा नाम बैलट में निकला है, आप उसको नहीं काट सकते हैं।

सभापति महोदय : नाम है, लेकिन टाइम ओवर हो गया।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि एक टन चीनी बनाने में कितना टन गन्ना लगता है ? दूसरे यह कि जो दाम नीति तय की जाती है उसमें किसान और मजदूरों का प्रतिनिधित्व है कि नहीं ? और तीसरा सवाल यह कि जो मिल मालिकों पर 81 करोड़ रुपये किसानों का बाकी है उस पर किसान को कितना सूद दिया जाता है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहां तक चीनी के उत्पादन का आपने जिक्र किया है उसमें रिकवरी के हिसाब से है। कहीं रिकवरी ज्यादा है, 12 परसेंट है, और कहीं साढ़े 8 और 9 परसेंट तक रह जाती है। तो रिकवरी के हिसाब से गन्ने की खपत होती है चीनी बनाने में, आम तौर पर नौर्मली ऐसा समझ लिया जाता है कि एक टन चीनी 10 टन गन्ने से बनती है। कुछ ऐसा मोटा हिसाब लगाया जाता है। लेकिन वैसे रिकवरी के हिसाब से चलता है उसके हिसाब से गन्ना लगेगा चीनी बनाने में।

श्री राम अवधेश सिंह : अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग रिकवरी है। बिहार में कितनी है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बिहार में भी सारी जगह एक सी रिकवरी नहीं है। कहीं कुछ है और कहीं कुछ है। बिहार में दाम-वैसे इस बार 12.25 से ले कर 12.50 तक रहे हैं।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : अब उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें अधिक दाम नहीं देंगी। जो आपने गन्ने की स्टेट्यूटरी प्राइस 10.50 रखी है उसको 15 रुपये कर देंगे ?

सभापति महोदय : हर मेम्बर इस तरह बीच में नहीं बोल सकता है। हम लोगों को रूल्स से गाइड होना चाहिये।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : पिछले साल बिहार में 12.25 रही है। इस साल 12.25 से ले कर 12.50 तक रही है।

श्री लखन लाल कपूर (पूर्णिया) : चीनी उद्योग को ले करके गन्ना उत्पादकों के साथ आये दिन उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ होता है और उसी के साथ-साथ उद्योग में लगे मजदूरों की जो हालत है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, असम, बंगाल, उड़ीसा आदि प्रदेशों में जो रिकवरी कम है और दक्षिण भारत में या महाराष्ट्र में रिकवरी ज्यादा है, इन दोनों में मिलान नहीं होता है। इसलिये चीनी आपने डी-कन्ट्रोल किया है, लंबी में 2 रुपये 30 पैसे दे रहे थे, इस समय 2 रुपये 75 पैसे से 2 रुपये 80 पैसे बिक रही है तो इसकी कीमत 2 रुपये 30 पैसे लाने के लिये आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

चीनी उद्योग और खेती को प्लान करने के लिये, जितनी हमारी आवश्यकता है, उसके अनुसार ही खेती करने के लिये क्या मिलों को नेशनलाइज करने की दृष्टि से आप कुछ सोचना चाहते हैं, या करना चाहते है ? यदि हां, तो कब तक करना चाहते हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कुछ जगहों में गन्ने की रिकवरी ज्यादा है और कुछ में कम है, इसके बहुत से कारण हैं। जैसा कि बताया महाराष्ट्र में गन्ने की रिकवरी 12 हो जाती है, वहां लम्बे समय तक खेतों में गन्ना रहता है। यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में टाइम कम लगता है, दूसरी फसल भी हो सकती है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता है, वहां पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिये वहां कास्ट ज्यादा आ जाती है, उनका खर्चा ज्यादा हो जाता है। क्योंकि बिहार में फैक्टरीज पुरानी लगी हैं पहले की हैं इसलिये वहां रिकवरी कम होती रही है। यही इसके कारण हैं।

19.10 hrs.

MOTION RE: INCREASING PLAY OF MONEY POWER IN ELECTIONS—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: Now let us take up Mr. Unnikrishnan's Motion. Professor Mavalankar.